



चक्रवाती तूफान "बिपरजॉय" का असर राजधानी जयपुर में मंगलवार को सबसे ज्यादा दिखा। अलसुबह से देर शाम तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा। अजमेर रोड पर कमला नेहरु नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश के कारण मुख्य सड़क दरिया बन गई। जलभराव के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ीं। सबसे ज्यादा तकलीफ दुपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीरों को हुई। हालांकि, सुबह से ही शहर के आसमान पर काली घनघोर घटाएं छाई हुई थीं, लेकिन शाम होते-होते तो शहर के लगभग हर इलाके में तेज बारिश शुरू हो गई और रूक-रूक कर देर रात तक पानी बरसता रहा। ऊपर दिया गया फोटो अजमेर रोड कमला नेहरु नगर का है।

इस साल कोई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से पूर्व लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो बात अलग है। सोलह जून 2023 के बाद, यानी 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के बाद, यदि लोकसभा की कोई सीट, संबंधित संसद की मृत्यु, इस्तीफा या अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली होती है, तो भारत का चुनाव आयोग ऐसी खाली सीट के लिए, उपरोक्त तिथि, 17 जून 2023 को या उसके बाद कोई उपचुनाव नहीं करवाएगा, क्योंकि ऐसी सीट पर चुने गए संसद का कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा। तथापि, जहाँ तक, 16 जून 2023 की कट ऑफ डेट से पहले लम्बित 5 खाली सीटों का सवाल है, कम से कम 3 सीटों, जो सिटिंग एम.पी. की मृत्यु के कारण खाली हुईं, के लिए आने वाले कुछ महीनों में चुनाव करवाने होंगे।

अदालतों में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत में लम्बित केसों की भयावह तस्वीर पेश की। डेटा में पता लगा कि जिला स्तर की एवं निचली अदालतों में 4,38,345 केस लम्बित हैं और सुप्रीम कोर्ट में 68,745 केस विचाराधीन हैं। जून में यह संख्या बढ़कर 1,2,023 हो गई है। जिला एवं निचली अदालतों में लम्बित मुकदमों में से 1.09 करोड़ (1,09,86,689) सिविल केस हैं 3.28 करोड़ (3,28,93,656) क्रिमिनल केस हैं।

भारत के 25 हाई कोर्ट्स में 60.5 लाख केस लम्बित हैं इनमें से 43.7 लाख क्रिमिनल केस हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार एक हाई कोर्ट के समक्ष औसतन 2,43,636 केस लम्बित हैं।

प. बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दखलंदाजी नहीं है। हम हाई कोर्ट के निर्देश में दखल नहीं देंगे। अपील खारिज।

सुप्रीम कोर्ट में प. बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की कलकत्ता हाई कोर्ट के दो आदेशों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हो रही थी। उनकी मुख्य शिकायत आगामी पंचायत चुनाव में संविधानसभा सीटों पर तुरंत प्रभाव से केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के आदेश के खिलाफ थी। हाई कोर्ट ने 15 जून को प. बंगाल राज्य चुनाव आयोग को इस संबंध में कदम पीछे हटाने के लिए लाता था।

आई.एस.आई. का सुनियोजित प्लान है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्टिविज्म इन द यू.एस." शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ये ग्रुप किस तरह से अमेरिका में अपना मजबूत आधार बना रहे हैं। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, "जब तक अमेरिकन सरकार की प्राथमिकताओं में खालिस्तान-संबंधी उग्रवाद और आतंकवाद पर नजर नहीं रहेगी, तब तक उन ग्रुपों को चिन्हित किया जाना संभव नहीं है, जो इस समय भारत के पंजाब में हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी-कभी ही वह चीज मिल पाती है, जिसे वह खोज नहीं रहा हो।" "रॉयटर्स" की एक रिपोर्ट में अनुसार, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आई.ए.एम.सी.) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगा। आई.ए.एम.सी. की वेबसाइट के

अमेरिका के जाने-माने थिंक टैंक "हडसन इन्स्टीट्यूट" ने मोदी की यात्रा के संबंध में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि, खालिस्तानी ग्रुप की निगरानी जब तक अमेरिका की प्राथमिकता में नहीं होगी, तब तक खालिस्तानी आंदोलनकारी कभी भी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।

अनुसार, यह "अमेरिका में भारतीय मुस्लिमों की हिमायत करने वाला सबसे बड़ा संगठन है।" "द सेंडे" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आई.ए.एम.सी. पाकिस्तान का दायें हाथ है। यह मानवाधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मामलों को लेकर भारत पर निरन्तर निशाना साधता आ रहा है। इसके अलावा, खुफिया सूत्रों ने समाचार एजेंसियों को यह भी बताया कि जिन दिनों मोदी अमेरिका में होंगे, वे जिन रास्तों से भी गुजरेंगे, उन रास्तों पर मोदी-विराधी पोस्टर लहराये जाने की भी योजना है। इसके

थानवाएं भड़कायी जा सकें। न्यूयॉर्क में 21 जून को "हाउडी डेमोक्रेसी" समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है तथा इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तथा संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का अध्यक्षता करेंगे। "हाउडी डेमोक्रेसी" के आयोजकों में से एक व्यक्ति के अनुसार, यह आयोजन भारत में "बढ़ते हुए अन्याय को अधिक उजागर करने के लिये" किया जा रहा है।

यह प्रधानमंत्री मोदी की छठी किन्तु प्रथम राजकीय यात्रा है तथा मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले टिवटर पर मोदी-विरोधी सामग्री वायरल करेगी। "मोदी का स्वागत नहीं" तथा "भारत को हिन्दू-प्रभुत्व एवं प्राधान्य से बचाओ" जैसे हैशटैग भी सृजित किये गये हैं ताकि मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले मोदी-विरोधी तथा भारत-विरोधी

हैं तथा एकता यात्राएँ (यूनिटी मार्च) आयोजित कर रहे हैं तथा इस प्रकार से वे मोदी के स्वागत का संदेश दे रहे हैं। बहुत से अमेरिकन नेताओं ने मोदी की वॉशिंगटन यात्रा को लेकर खुशी एवं उत्साह व्यक्त किया है। ज्ञातव्य है कि ऐसी संभावना भी है कि मोदी दो बड़े रक्षा-सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने मोदी की अमेरिका यात्रा पर खुशी है, (अमेरिका में) अत्यधिक कुशा हो माहौल है। आपने गवर्नरों, सैनेट के सदस्यों, स्टेट लिजिस्लेटर्स, इन्डस्ट्री, अकेडेनिया, थिंक-टैंक तथा हवाई से लेकर अलास्का तक, अमेरिका के सभी हिस्सों में फैले भारतीय-अमेरिकनों की ओर से मोदी के स्वागत के संदेश एवं बयान देखे ही होंगे। यह यात्रा एक ज्वन के साथ ही तात्विक पहलू सम्पन्न होगी तथा दोनों देश एक-दूसरे के पूरक होंगे।

राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडन इनकम टैक्स चोरी के दोषी करार दिये गये

अमेरिका की जिला अदालत ने हंटर बाइडन को ड्रस लेने का आदी मानते हुये उन्हें अवैध हथियार रखने का भी दोषी करार दिया है

वॉशिंगटन, 20 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को करारा झटका लगा है। उनके बेटे हंटर बाइडन को संघीय आयकर (इनकम टैक्स) का भुगतान न करने, अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में दोषी करार दिया गया है। अमेरिका के डेलावेयर की एक जिला अदालत में दायर आरोप पत्र में राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर पर संघीय आयकर का भुगतान करने में विफल रहने और अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है, हालांकि उन्होंने न्याय विभाग के साथ एक समझौता कर लिया है।

मंगलवार को सार्वजनिक किए गए समझौते के हिस्से के रूप में हंटर बाइडन, अपराधों के लिए गुनाह कबूलेंगे और मादक द्रव्य के उपयोगकर्ता के रूप में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में उनके (हंटर के) अभियोजक के साथ एक

हालांकि, इस मामले में हंटर बाइडन को किसी प्रकार की कानूनी सजा मिलने की संभावना बहुत कम है क्योंकि, उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौता कर लिया है। संभव है कि, अमेरिकी न्याय विभाग हंटर बाइडन पर इस मामले में भारी अर्थदण्ड लगायेगा।

हंटर बाइडन ने स्वीकार किया है कि, वे 2015 में अपने भाई ब्यू बाइडन की मौत के बाद नशे की लत में पड़ गये थे।

समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है। अदालत में आरोप पत्र दायर करते समय किसी संघीय अपराध मामले का समाधान किया जाना कुछ असामान्य है, हालांकि यह पूरी तरह से असुना नहीं है। यह समझौता बाइडन के दूसरे बेटे

की न्याय विभाग द्वारा लंबे समय से की जा रही जांच को समाप्त करेगा। हंटर ने 2015 में अपने भाई ब्यू बाइडन की मौत के बाद नशे की लत से जुझना स्वीकार किया है। यह समझौता एक ऐसे मुकदमे को भी टालता है, जो दिनों या

हफ्तों तक व्हाइट हाउस के लिए परेशानी पैदा करने वाली सुविधियां बनाता। व्हाइट हाउस ने हालांकि न्याय विभाग से अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश की है।

गौरतलब है कि, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन पर एक विदेशी गैस कंपनी के सी.ई.ओ. से अरबों रुपये की रकम रिश्वत के तौर पर लेने के भी आरोप लगे हैं। बाइडन पर आरोप है कि, उन्होंने अमेरिका में काम करने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आरोपों से क्लीनचिट दिलाने की एजब में मोटी रकम रिश्वत के तौर पर ली थी। इस सब आरोपों के बाद माना जा रहा है कि, इन आरोपों के कारण राष्ट्रपति बाइडन को आगामी राष्ट्रपति चुनावों में भारी हानि उठानी पड़ सकती है।

बारिश के कारण सावन से पहले ही राजस्थान के 67 बांध लबाबलब हुये

मौसम विभाग के अनुसार बीते चार दिनों में 66 से अधिक केंद्रों पर 100 एम.एम. से अधिक बारिश दर्ज की गई है

जयपुर, 20 जून। सायकलोन बिपरजॉय के कारण बारिश ने राजस्थान में कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पिछले चार दिनों में सायकलोन बिपरजॉय के चलते हुई भारी बारिश ने राजस्थान के 67 बांधों को लबाबलब भर दिया है, ऐसी स्थिति शायद पहले कभी नहीं देखी गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात के चलते पिछले चार दिनों में राज्य को 660 मेगा क्यूसेक मीटर (एम.सी.एम.) से अधिक पानी मिला। राज्य के बांधों में 15 जून को 5384.38 एम.सी.एम. पानी था, जो 19 जून की शाम तक 6045 एम.सी.एम. से अधिक हो गया है।

जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 66 से अधिक केंद्रों

राज्य के बांधों में 15 जून को 5384.38 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) पानी था, जो 19 जून की शाम तक 6045 एम.सी.एम. से अधिक हो चुका है।

प्रदेश जल संसाधन विभाग के अनुसार, पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश के चलते सात जिलों अजमेर, जालोर, पाली, सिराही, राजसमंद, उदयपुर और टोंक के लगभग 67 छोटे और बड़े बांध अपनी क्षमता से अधिक भर गए हैं।

राज्य में 24-25 जून से फिर कुछ दिनों तक बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है।

100 मि.मी. से अधिक बारिश दर्ज की गई। अधिकारी ने कहा, पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश के चलते सात

जिलों अजमेर, जालोर, पाली, सिराही, राजसमंद, उदयपुर और टोंक के लगभग 67 छोटे और बड़े बांध अपनी क्षमता से

2025 तक टर्कों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद, ड्राइवरों के केबिन को एयरकन्डीशन्ड बनाने की मेरी तीव्र इच्छा थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ऐसा करने से टर्कों की कीमत बढ़ जायेगी। आज मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिये कि सभी टर्कों में एस.सी. वाले केबिन होंगे।" वे महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स द्वारा आयोजित "देश चालकर-रिगनाइज दोज हू मूव इंडिया" नामक को संबोधित कर रहे थे।

गडकरी ने कहा कि भारत में ड्राइवरों की कमी है, जिसके कारण उन्हें प्रतिदिन 14-16 घंटे टर्क चलाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, "अन्य देशों में, टर्क ड्राइवरों की इयूटी के घंटों की अधिकतम सीमा की पाबंदी है।"

मंत्री महोदय ने इस काम के लिये किसी अंतिम तिथि का उल्लेख तो नहीं किया कि लोग टर्कों में ए.सी. लागू करने की उम्मीद कब तक कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह 2025 से शुरू हो जायेगा।

मंत्री लॉजिस्टिक के खर्च में कमी करने के बारे में भी बोले तथा उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत में इसे कम करने की जरूरत है ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि इससे लिये अच्छी क्वालिटी की सड़कें तथा टर्क बहुत जरूरी हैं।

कांग्रेस ने नड्डा व अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि, इन नेताओं ने राहुल गांधी का एनिमेटेड वीडियो जारी कर उन पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है

बैंगलुरु, 20 जून (वार्ता)। कर्नाटक कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और पार्टी के आई.टी. सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ शहर की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इसके अलावा चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो जारी करने के लिए भी शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (के.पी.सी.सी.) के प्रवक्ता रमेश बाबू ने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 505 (2), 553 (ए), 120 (बी), 34

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रमेश बाबू ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि, भाजपा नेता अमित मालवीय ने गत 17 जून को अपने आधिकारिक टिवटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि, राहुल गांधी भारत के बाहर अपनी यात्राओं पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा कि मालवीय ने 17 जून को अपने आधिकारिक अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी भारत के बाहर अपनी यात्राओं पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

खड़गे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गांधी

देश को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे झूठ की फैक्टरी को बंद करने का फैसला किया है। भाजपा इससे बच सकती, क्योंकि वह अनकी सरकार थी। तब तथ्य-जांच इकाई बंद हो गई थी। अब तथ्य-जांच इकाई को मजबूत किया जाएगा। मैं (प्रियांक खड़गे) पहले ही मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूँ।

पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई हिरासत में लिये गये

बैंगलुरु, 20 जून। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति के विषय पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को एक-दूसरे पर निशाना साधा। दोनों ही दलों की ओर से राज्य के निशाने हिस्सों में प्रदर्शन भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत कई भाजपा नेताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिद्धरमैया सरकार गरीब परिवारों को 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल प्रदान करने में विफल रही है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हुबली में कहा, 80 करोड़ देशवासियों को हम 5 किलो मुफ्त चावल दे रहे हैं इसलिए बाकी 60 करोड़ लोगों के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। यह सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में जो 5 किलो से चावल दिया जा रहा है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। आप (कर्नाटक सरकार) भी व्यवस्था करो और दे दो। सी.एम. सिद्धरमैया ने कहा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) ने राज्य को खाद्यान्न आपूर्ति करने पर सहमति जताई थी। 13 जून को उपभोक्ता मंत्रालय ने एफ.सी.आई. की खाद्यान्न की आपूर्ति रोकने के लिए पत्र लिखा।

क्या अमेरिका भारत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस नई वैश्विक व्यवस्था में भारत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नए मंच पर भारत को पहले ही किसी हद तक स्वीकार किया जा चुका है। चार देशों की क्वांट प्रक्रिया में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी है। क्वांट, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चारों कोनों के देशों का एक टुक है जो अब काफी मजबूत हो गया है। भारत क्वांट की संयुक्त सैन्य कवायदों में शामिल होता है। विरोधी देश अक्सर इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी ओर कुछ तकनीकी अभियान भी इस यात्रा में पूरे होंगे जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है जनरल इलेक्ट्रिक का प्रस्ताव। यह कंपनी अमेरिका की सेना के अत्याधुनिक विमानों के लिए इंजन बनाती है। अभी तक यह तकनीक विपक्षी यूरोप के कुछ खास मित्रों को ही उपलब्ध थी। पहली बार यह तकनीक भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी को दी जाएगी ताकि भारत में इन इंजन का निर्माण हो। यह दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिक सहयोग का अंग है।

इस दौरान प्रधानमंत्री एलन मस्क से भी मिलेंगे। मुलाकात का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बेटरी के निर्माण में निवेश हेतु मस्क को रिझाना। इलेक्ट्रिक जलवायु परिवर्तन से जंग में सहायक होंगी। वर्तमान में प्रोफाइल है और कुछ ही देशों को इतना महत्व मिलता है।

इधर यूक्रेन वॉर शुरू करने से पहले रूस और चीन ने यही किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की थी कि दोनों "बैट फ्रेंड्स" हैं। अब भारत और अमेरिका की बारी है, एक दूसरे को "बैट फ्रेंड" बुलाने को।

22 जून ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नारे के साथ सामने आने की जरूरत है। कई बाधाएँ हैं और अहं के टकराव हैं। मोदी का मुकाबला करने से पहले विपक्ष को इसे सुलझाना पड़ेगा।